



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 17 जुलाई, 2003/26 अगस्त, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 17 जुलाई, 2003

संख्या वि० स०-विधायन-अ० मांगे/1-63/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2003 (2003 का

विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 17 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर-स्थापित हो चुका है, मर्यादावारण हो सूचनायें प्रसाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1999-2000 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) संक्षिप्त नाम । अधिनियम, 2003 है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 33,16,82,26,856 रुपए (तीस अरब, सोलह करोड़, ब्यासी लाख, दस हजार, आठ सौ छप्पन रुपए) है, वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं में सम्बन्धित प्रभागों का चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1999-2000 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 33,16,82,26,856 रुपए की और राशि प्राधिकृत करना ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपए	रुपए	रुपए
4	सामान्य प्रशासन (पूँजी)	35,55,36,858	—	35,55,36,858
7	पुलिस और (राजस्व)	3,55,58,116	—	3,55,58,116
8	सम्बद्ध संगठन शिक्षा, खेल, (राजस्व)	83,34,36,568	—	83,34,36,568
9	कला और संस्कृति स्वास्थ्य और (राजस्व)	5,05,68,857	—	5,05,68,857
10	परिवार कल्याण लोक निर्माण (राजस्व)	93,50,52,356	—	93,50,52,356
12	सिंचाई और बाढ़ (राजस्व)	8,21,38,262	—	8,21,38,262
17	नियंत्रण सड़कें और पुल (राजस्व)	6,45,05,898	—	6,45,05,898
18	(पूँजी) आपूर्ति उद्योग और (पूँजी)	10,60,52,909	—	10,60,52,909
20	खनिज ग्रामीण विकास (पूँजी)	89,025	—	89,025
23	जल और विद्युत (राजस्व)	1,16,649	—	1,16,649
27	विकास श्रम और रोजगार (पूँजी)	9,10,73,117	—	9,10,73,117
28	जलापूर्ति, सफाई, (राजस्व)	81,256	—	81,256
29	आवास और नगर (पूँजी)	27,16,76,519	—	27,16,76,519
31	विकास वित्त (राजस्व)	5,87,01,549	—	5,87,01,549
	(पूँजी)	12,47,39,121	20,62,53,591	33,09,92,712
		—	29,81,41,15,114	29,81,41,15,114
	जनजातीय (राजस्व)	13,85,31,091	—	13,85,31,091
	विकास			
	जोड़	3,14,78,58,151	30,02,03,68,705	33,16,82,26,856

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1993-2000 के दौरान अनुदान और वित्तियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के वित्तियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

बीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : 17 जुलाई, 2003.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल नम्बर फिन0 ए0 डी0 (6)-2/2002]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वित्तियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2003 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year, 1999-2000 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2003.

Authorisation of a further sum of Rs 33,16,82,26,856 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year, 1999-2000.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 33,16,82,26,856 (thirty three hundred sixteen crores, eighty two lakh, twenty six thousand, eight hundred fifty six rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year, 1999-2000 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year, 1999-2000.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 Number of Demand	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
4	General Administration (Capital)	35,55,36,858	—	35,55,36,858
7	Police and Allied Organisation (Revenue)	3,55,58,116	—	3,55,58,116
8	Education, Sports, Art and Culture (Revenue)	83,34,36,568	—	83,34,36,568
9	Health and Family Welfare (Revenue)	5,05,68,857	—	5,05,68,857
10	Public Works (Revenue)	93,50,52,356	—	93,50,52,356
12	Irrigation and Flood Control (Revenue)	8,21,38,262	—	8,21,38,262
17	Roads and Bridges (Revenue)	6,45,05,898	—	6,45,05,898
18	Supplies, Industries and Minerals (Capital)	10,60,52,909	—	10,60,52,909
20	Rural Development (Capital)	89,025	—	89,025
23	Water and Power Development (Capital)	1,16,649	—	1,16,649
27	Labour and Employment (Revenue)	9,10,73,117	—	9,10,73,117
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development (Capital)	81,256	—	81,256
29	Finance (Revenue)	27,16,76,519	—	27,16,76,519
31	Tribal Development (Capital)	5,87,01,549	—	5,87,01,549
		12,47,39,121	20,62,53,591	33,09,92,712
		—	29,81,41,15,114	29,81,41,15,114
		13,85,31,091	—	13,85,31,091
	Total ..	3,14,78,58,151	30,02,03,68,705	33,16,82,26,856

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year, 1999-2000.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 17 July, 2003.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

[Finance Department File No. Fin. A.D. (6)/2/2002]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Bill, 2003 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.